

खाली हाथ लौटे चीन के राष्ट्रपति रूस की यात्रा से!

यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए उनका प्रस्ताव, यूक्रेन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन ने एक सिरे से पूर्णतया अस्वीकार किया

—अंजन राय—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 22 मार्च। मध्य-पूर्व में ईरान और सऊदी अरब के बीच एक दीर्घकालीन विरोध को हल करने में कूटनीतिक सफलता प्राप्त कर फूले नहीं समा रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मास्को दौर के लेकर माना जा रहा था कि वह वहां भी ऐसी ही सफलता प्राप्त करेंगे।
यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ है, रूस कूटनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ने के बाद चीन पर लगातार निर्भर रहा है। इसके भारत के लिए भी मायने हो सकते हैं क्योंकि विश्व में कहीं भी चीन के हितों को लेकर होने वाले किसी भी संघर्ष में बीजिंग का समर्थन करने में रूस का आधिकारिक झुकाव रहेगा। चीन इसके बदले में भारत के साथ लगती अपनी सीमा पर कलह बढ़ाने में अधिक सक्रिय होगा और इस प्रकार वह अपनी गिरी हुई घरेलू स्थिति से विश्व

- यूक्रेन ने कहा, चीन का शांति प्रस्ताव रूस के आक्रमण को उचित ठहराने का प्रयास है। तथा, रूस द्वारा यूक्रेन की भूमि को हथियाने को "लैजिटाइज़" कराने का प्रयास है।
- रूस ने अपनी मध्यस्थता से सऊदी अरब व ईरान की पुरानी दुश्मनी खत्म करायी है, अतः विश्व को काफी आशा थी कि, चीन, रूस व यूक्रेन के बीच भी शांति स्थापित करवायेगा, पर, राष्ट्रपति शी की रूस यात्रा, इस मामले में पूर्णतया निराशाजनक रही।
- इसी निराशा के कारण, रूस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कटाक्ष किया, चीन केवल अपना खुद का मित्र है, किसी और का मित्र नहीं हो सकता।

का ध्यान डायवर्ट कर सकेगा।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि यूक्रेन से मुलाकात को लेकर शी के बहुप्रचारित मास्को दौर की पृष्ठभूमि में चीन ने यूक्रेन में शांति स्थापना के लिए एक कूटनीतिक पेपर प्रकाशित किया था। शी के मास्को दौर के संदर्भ में पुतिन ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि यूक्रेन संकट को हल करने में चीन के प्रस्ताव अहम होंगे।
तथापि, चीन के प्रस्तावों को कहीं से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली

और खासतौर पर, यूक्रेन से तो बिल्कुल भी नहीं। यूक्रेन ने इनके प्रकाशन के साथ ही इनको यह कहकर आलोचना की थी कि चीन का पेपर सिर्फ रूस की स्थिति मजबूत करने के लिए है। आलोचना इस बात को लेकर थी कि पेपर में यह उल्लेख किए बिना युद्ध विराम का आ आ किया गया है कि रूस के सैनिकों को यूक्रेन के क्षेत्र से बाहर चले जाना चाहिए।
यूरोपीयन यूनियन ने चीन के प्रस्तावों पर विचार करने की जरूरत नहीं समझी और उन्हें खारिज कर दिया। उसने कहा कि इनका उद्देश्य यूक्रेन में भूमि पर कब्जा करने के रूस के इरादों को और मजबूत करना पर है। इसी तरह, अमेरिका ने यह कहते हुए इन्हें खारिज कर दिया कि युद्ध विराम की चीन की घोषणा का उद्देश्य रूस को पुनर्संगठित होने और अपना आक्रमण पुनः शुरू करने के लिये समय उपलब्ध करवाना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कूड ऑयल सस्ता हो रहा है, पर पेट्रोल, डीजल के दाम सिर्फ बढ़ रहे हैं'

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 22 मार्च। कांग्रेस प्रवक्ता प्रो. गौरव वल्लभ ने कहा है कि मोदी सरकार में ईंधन की गतिशील कीमतें बिल्कुल ऐसी हैं "मानो चित हम जीते, पट तुम हारो।" उन्होंने कहा कि ईंधन के कीमत-निर्धारण की नीति के

- कांग्रेस की तरफ से पार्टी प्रवक्ता प्रो. गौरव वल्लभ ने पूछा कि, पेट्रोल, डीजल के दाम गतिशील हैं, पर ये लगातार चढ़ क्यों रहे हैं, कभी घटते क्यों नहीं।

तहत, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जब-जब कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तो उसका लाभ अंतिम/मूल उपभोक्ता को नहीं होता।
गौरव ने कहा, "हम एक्ससाइज ड्यूटी को कम करने के लिये नहीं कह रहे हैं, जो पेट्रोल के मामले में मई, 2014 की 9.2 रु. लीटर से अब 19.9 रु. लीटर हो गई है तथा डीजल की एक्ससाइज ड्यूटी 3.46 रु. से

भारत ने पलटवार किया ब्रिटेन पर

—श्रीनन्द झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 22 मार्च। भारत सरकार ने नई दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमिशन तथा ब्रिटिश हाई कमिश्नर के आवास के बाहर के सुरक्षा बैरियर्स हटा दिये हैं। सरकार की इस कार्यवाही को बदले की कार्यवाही के रूप में देखा जा रहा है।
रविवार को, लंदन-स्थित भारतीय उच्चायोग पर लगा भारतीय झंडा किसी खालिस्तान-समर्थक प्रदर्शनकारी ने हटा दिया था। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, भारत सरकार ने भारत में ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया था तथा लंदन की उस घटना को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया था। भारतीय

- नई दिल्ली स्थित ब्रिटेन के हाई कमिशन कॉम्प्लेक्स से सुरक्षा वापस ली।
- जैसा कि विदित ही है, लंदन में भारतीय कमिश्नर के कॉम्प्लेक्स पर खालिस्तान समर्थकों ने तोड़-फोड़ की तथा भारत का झण्डा उतार कर खालिस्तान का झण्डा फहरा दिया था।
- भारत इस कृत्य को ब्रिटेन की प्रशासनिक शिथिलता तथा हाई कमिशन परिसर की सुरक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान न देना मानता है।

तैसा' कदम पर कोई अधिकृत प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने भी "सुरक्षा संबंधी मामलों" (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CAT-22 CRACKED!!

Congratulations to T.I.M.E. Jaipur Students!!

147 T.I.M.E. Jaipur students have secured 1019 IIM calls in CAT-22

			
			
			

... (many more names) ...

क्या आपको कम सुनाई देता है?

कान की मशीनें स्पीच थेरेपी फ्री सुनाई की जाँच

PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
www.perfecthearingsolutions.com

सख्त मल (कब्ज) व पेट की परेशानियों का आयुर्वेदिक उपचार

जागृवी चूर्ण

www.jagraviherbal.com

आंध्र में मु.मंत्री व पूर्व मु.मंत्री एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की होड़ में

वाय.एस.आर. कांग्रेस के नेता व वर्तमान मु.मंत्री जगन रेड्डी ने पूर्व मु.मंत्री चन्द्रबाबू नायडू पर 3 सौ सत्तर करोड़ रुपये डकारने का सीधा आरोप लगाया

—लक्ष्मण वेंकट कुची—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 22 मार्च। तेलंगाना या कर्नाटक, जहाँ प्रमुख राजनैतिक दलों के बीच की बड़ी राजनैतिक लड़ाइयाँ राष्ट्रीय चर्चाओं का विषय बन रही हैं, के विपरीत, आंध्र प्रदेश इस मामले में ज्यादा चर्चित नहीं है, हालाँकि सत्तारूढ़ वाय.एस.आर.सी.पी. तथा तेलुगु देशम पार्टी के बीच की लड़ाई भी उतनी ही उग्र और भीषण स्तर पर पहुँच रही है तथा आरोपों-प्रत्यारोपों का सिलसिला रोज़ की बात है। अगर विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री वाय.एस. जगमोहन रेड्डी सरकार का शासन निरंकुश एवं फासिस्ट है जिसमें जजों तक को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री वाय.एस. जगन मोहन रेड्डी ने पहली बार पिछले मुख्यमंत्री का नाम लेते हुये, उन पर 370 करोड़ रु. से अधिक के घोटाले में सीधे तौर

पर लिप्त होने का आरोप लगाया है।
पूर्व मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू ने दुख व्यक्त करते हुये कहा है कि राज्य में "आपातकाल जैसी" स्थिति चल रही है तथा सरकार सभी मोर्चों पर विफल हो चुकी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री राज्य को पीछे धकेल रहे हैं। सत्तारूढ़ दल ने इस आरोप की उतनी ही तीखी प्रतिक्रिया दी है।
आंध्र प्रदेश में प्रमुख दल चुनावी मोड़ में आ चुके हैं। आंध्र के प्रमुख विरोधी दलों के बीच मीडिया में उग्र टकराव तथा उत्तेजित बहसें हो रही हैं, वहीं जमीन पर भी उतेजनापूर्ण टक्करें चल रही हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष लोकसभा चुनावों के साथ ही होने हैं तथा इसलिये वहाँ राजनैतिक हलचलें बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ ही भाजपा यह टोह ले रही है कि क्या वह आंध्र में प्रवेश कर सकती है। भाजपा सैलिब्रिटी को अपने साथ लाकर, जनता तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। भाजपा सुपर

CAT-22 IIM Calls Summary

IIM A	IIM B	IIM C	IIM L	IIM I	IIM S
8	5	14	17	28	20
36	53	54	50	47	32
52	42	50	122	54	

CAT-2023/24 GMAT / CMAT Classroom / Online Live Batches available

DO WE NEED TO SAY MORE?

Attend Seminar & Write Scholarship Test

T.I.M.E. Talent Search Exam

Exam Fee - Rs.100/-

Every Sunday @ 10 am

Get upto 100% Scholarship*

Triumphant Institute of Management Education Pvt. Ltd.

www.time4education.com | jaipur@time4education.com

Civil Lines | JLN Marg | Vaishali Nagar | Vidyadhar Nagar
7230810003 | 8094411666 | 7232893893 | 8233220422

188 Centres in 97 Cities

'मैंने कभी लंदन, पेरिस, अमेरिका व जर्मनी से हस्तक्षेप करने की बात नहीं कही'

राहुल गांधी ने एक इन्टरव्यू में कहा, "वे मानते हैं कि, भारतीय प्रजातंत्र के संकट का समाधान भी भारत ही निकालेगा, कई और नहीं"

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 22 मार्च। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र के संकट के संबंध में कहा कि यह हमारे देश की समस्या है और इसका समाधान हमारे देश के भीतर ही खोजना होगा। इसका समाधान बाहर से नहीं आ सकता।
उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि जैसा सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके विपरीत उन्होंने लंदन, पेरिस, अमेरिका या बर्लिन की सरकारों से कभी भी हस्तक्षेप करने को नहीं कहा।
इस सप्ताह की शुरुआत से ही चल रही इन अटकलों के बारे में कि यदि विपक्ष गौतम अडानी के प्रकरण में जाइंट पालियामेन्टरी कमेटी (जे.पी.सी.) से जांच की अपनी मांग को वापस ले लेता है तो भाजपा लोकतंत्र पर की गई उनकी टिप्पणी पर माफी

- चर्चा है कि, अगर कांग्रेस अडानी के प्रकरण में जे.पी.सी. की मांग त्याग देगी तो, सरकार भी राहुल द्वारा माफी मांगने की जिद छोड़ देगी।
- इस चर्चा पर राहुल ने कहा, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं, हम इस सौदे के लिये तैयार नहीं हैं तथा जे.पी.सी. के गठन की मांग कभी नहीं छोड़ेंगे।
- जयराम रमेश ने राहुल के कथन का समर्थन करते हुए कहा, अडानी आखिर इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गये कि, उनको बचाने के लिये संसद नहीं चलने दी जा रही तथा जे.पी.सी. का गठन नहीं हो रहा।

और सरकार से प्रश्न पूछे जाएं हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न केवल जे.पी.सी. मानेंगे की मांग को वापस ले लेगी, राहुल ने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों मुद्दे एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। "हम ऐसी किसी भी सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं हैं।"
कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञों का एक पैनल अडानी केन्द्रित है, जो अडानी केन्द्रित है, जो सिर्फ अडानी से ही प्रश्न पूछेगा "लेकिन हम अडानी से प्रश्न पूछना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी

ही पूछ सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल उन पर विचार तक नहीं करेगा।" उन्होंने आशंका जतायी की सुप्रीम कोर्ट का पैनल सरकार को क्लीन चिट दे देगा।
उन्होंने यहां ए.आई.सी.सी. मुख्यालय पर बुधवार को आयोजित एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वह तीन प्रश्न प्रतिदिन के हिसाब से मोदी से इस बारे में अब तक 100 प्रश्न पूछ चुके हैं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका के 186 बैंक धराशायी होने की आशंका

वॉशिंगटन/नई दिल्ली, 22 मार्च। दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था अमेरिका इस समय गंभीर बैंकिंग संकट से जूझ रहा है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक से शुरू हुआ संकट अब तक तीन बैंकों को लील चुका है। ताजा रिपोर्ट की मानें तो अमेरिका के 186 बैंक इस कतार में खड़े हुए हैं। अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व बीते साल अप्रैल से आक्रामक रूप से ब्याज दरें बढ़ रहा है। अब पूरे देश सहित दुनिया भर की निगाहें बुधवार रात होने वाली फेड की बैठक पर नही फेड का ब्याज फिर ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी करता है तो यह वहां के बैंकिंग सिस्टम के लिए किसी तबाही से कम नहीं होगा। अमेरिका से यूके तक बैंकिंग संकट क्या खत्म हो गया है? जवाब है नहीं। उल्टा अगर यूएस फेड आज ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी कर देता है, तो अमेरिका में एक के बाद एक बैंक भरभराकर गिरने लगेंगे। इस बैंकिंग संकट की जड़ प्रमुख ब्याज दरों में हुआ इजाफा ही है।